

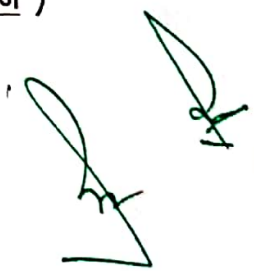
चिकित्सा स्नातक (MBBS) पाठ्यक्रम में N.R.I. कोटे हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. 10वीं की अंक सूची
2. 12वीं की अंक सूची
3. एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा (NEET) का प्रवेश पत्र
4. एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा (NEET) का अंक सूची
5. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

N.R.I. से संबंधित दस्तावेज हेतु देखें छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2018 के नियम 13 का उपनियम (स) (संबंधित पेज संलग्न है)।

संलग्न :-

1. छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2018 संबंधित नियम 13 के ( 03 पेज ) आवश्यक होने पर पूरे नियम का वेबसाईट पर अवलोकन करें।
2. N.R.I. अधिसूचना दिनांक 30 जुलाई 2017 ( 04 पेज )
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश WP(C) 689 / 2017 ( 07 पेज )



11. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्धदण्ड बंधपत्र :- द्वितीय काउंसिलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि/अंतिम आबंटन के प्रवेश उपरान्त उपरोक्त विवरणिका में उल्लेखित नियमानुसार सीट के परित्याग पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम के माध्य से सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 20,00,000/- (रुपये बीस लाख मात्र) होगी।

बीडीएस पाठ्यक्रम के मध्य से सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र) होगी।

विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फीट छात्र यदि मेडिकली अनफीट (Medically Unfit) हो जाता है जिसे राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफीट बताया जाता है तो बंधपत्र (वॉण्ड) राशि में छूट शासन द्वारा दी जा सकेगी।

12. प्रवेश रद्द करना :- यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान स्वतः बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। संस्था प्रमुख के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यालय संचालक चिकित्सा शिक्षा में अपील कर सकेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।

13. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता एवं नियम जानकारी :-

(अ) पात्रता : केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो अथवा राज्य के बाहर का निवासी हो और जिसने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो

तथा

जिसने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बारहवीं कक्षा की परीक्षा या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के माध्यमिक शिक्षा मण्डलों की समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी विषयों में उत्तीर्ण की हो तथा विषय भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी में अनारक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी में कुल अंक न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्जित किए हों

## तथा

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जिराने प्रवेश परीक्षा (NEET नियम 02 (क) (ख) के अनुरूप) में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशतमक (Percentile), आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशतमक (Percentile) तथा अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन संवर्ग के अभ्यर्थी के लिये 45 प्रतिशतमक (Percentile) अंक अर्जित किये हों अथवा NEET प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता अंक, जो भी न्यूनतम होगा वह मान्य किया जायेगा। (भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक नहीं होंगे) यदि NEET के समस्त श्रेणी/किस्मी श्रेणी में प्रतिशतमक (Percentile) में केन्द्र शासन द्वारा कमी की जाती है तो वह मान्य होगी।

- (ब) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि, आरक्षण एवं शुल्क :- छ.ग. राजपत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4 प्रकाशन क्रमांक 279 दिनांक 03 जुलाई 2017 के अनुसार प्रत्येक निजी महाविद्यालय की 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश की सीटों में संस्थावार प्रत्येक संस्था की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

शुल्क :- अप्रवासी भारतीय श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेश मुद्रा में भुगतान करना होगा।

अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :- प्रत्येक निजी व्यावसायिक निजी महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

- (स) अप्रवासी भारतीय नियतांश के लाभ हेतु पान्नता एवं दस्तावेज :-

1. अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का अभ्यर्थी से अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक में माता या पिता पक्ष से रक्त संबंध की पुष्टि करता हो (जैसे : संबंध पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता) इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
3. विदेश में निवास का प्रमाण हेतु वहाँ का ग्रीन कार्ड/कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैध वीसा सहित/नागरिकता संबंधित सक्षम दस्तावेज/181 दिन अथवा अधिक का कार्य प्रमाण हेतु दस्तावेज/अन्य कोई सक्षम दस्तावेज जो इस बिन्दु की पूर्ति करता हो।

3. एन.आर.ई./एन.आर.आई./समकक्ष बैंक एकाउण्ट की स्टेटमेन्ट कॉपी।
4. वर्क परमिट जो कि न्यूनतम 181 दिन अथवा अधिक का हो/ग्रीन कार्ड-धारी की कॉपी जो कि बिन्दु क्र. 02 के अनुसार पूर्ति करता हो।
5. प्रायोजक की आय, सम्बंधित पाठ्यक्रम के शुल्क देने योग्य हो तथा शुल्क का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त नियम 7 (xxi) में उल्लेखित दस्तावेजों की भी आपूर्ति करना होगा।

(द) अप्रवासी भारतीय नियतांश में प्रवेश की अंतिम तिथि :- प्रत्येक निजी व्यावसायिक निजी महाविद्यालय, प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिन के पूर्व अप्रवासी भारतीय नियतांश में अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा, जो कि अप्रवासी भारतीय नियतांश की अंतिम तिथि होगी।

14. केन्द्र शासन द्वारा अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा भारतीय दंत परिषद अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, शुल्क इत्यादि अन्य संबंधित जारी किये गये आदेश एवं निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।

15. कठिनाइयों का निराकरण :- इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।

16. प्रावीण्य सूची की समाप्ति :- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटें कालातीत हो जायेगी।

17. निरसन :- इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से "छत्तीसगढ़ चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा स्नातक/भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) प्रवेश परीक्षा" से संबंधित पूर्व के समस्त नियम निरसित हो जाएंगे तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017 — आषाढ 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017.

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4. — राज्य शासन एतद्वारा राज्य निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय नियतांश के संदर्भ में पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 के प्रकरण में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जिसमें निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पीपीसी) में अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु विहित नियमों को अनिवार्य किया गया है, के अनुपालन में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

## नियम

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार :- (1) ये नियम निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय नियतांश नियम, 2017 कहलायेंगे.  
(2) ये नियम 04-07-2017 से प्रवृत्त होंगे.  
(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- प्रयोज्यता :- ये नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति के पश्चात् खोले गये समस्त निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पीपीसी) पर लागू होंगे.
- परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-  
(क) “अप्रवासी भारतीय (संक्षेप में एन.आर.आई.)” का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/ अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया है.  
(ख) “निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (संक्षेप में पी.पी.सी.)” से अभिप्रेत है चिकित्सा/दंत/निर्सिग/फिजियोथेरेपी या जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका संचालन निजी प्रबंधन/कंपनी/न्यास/निकाय द्वारा किया जाता हो तथा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध हो.  
(ग) “आरक्षण नीति” से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं हेतु समय-समय पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति.

4. अप्रवासी भारतीयों का निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पी.पी.सी.) में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान.—

- (1) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), कुल सीटों के 15% सीटों को अप्रवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) द्वारा एन. आर. आई. श्रेणी के बीच से उनके मेरिट के आधार पर भर सकेगा।
- (2) गणना के पश्चात् अपूर्णाक को संबंधित निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.) के पक्ष में अगले उच्चतर अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।
- (3) एन. आर. आई. श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा।
- (4) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), इस आशय की अग्रिम सूचना वेबसाइट एवं अन्य लोकप्रिय साधनों के माध्यम से घोषित करेगा।
- (5) राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी।
- (6) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिवस के पूर्व एन. आर. आई. नियतांश में विद्यार्थियों को प्रवेश देगा जो कि एन. आर. आई. श्रेणी हेतु अंतिम तिथि होगी। इस अंतिम तिथि के पश्चात् सीटों को रिक्त घोषित किया जायेगा और मुक्त श्रेणी के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

5. कठिनाइयों का निराकरण.— इन नियमों के निष्पादन में कोई कठिनाई उद्भूत होने की दशा में, मामले को संचालक, चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट किया जायेगा जो छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण का निर्णय करेगा। संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा (डी. एम. ई.) का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 3rd July 2017.

No. F-21-10/2017/Nine/55-4.—The State Government hereby makes the following Rules for the admission into Government and Private Nursing College of the State :-

### **NOTIFICATION**

In pursuance of the order of the Hon'ble Supreme court of India in the case of P.A. Inamdar v. State of Maharashtra, (2005) 6 SCC 537, which mandated to prescribe rules for fixing Non-Resident Indian quota in Private Professional Colleges (PPC), State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

### **RULES**

1. **Short title, commencement and extent.** - (1) These rules may be called the Chhattisgarh Non-Resident Indian Quota in Private Professional Colleges Rules, 2017.  
(2) It shall come into force ~~4/7/2017~~ (Date)  
(3) It shall extend to the whole of State of Chhattisgarh.
2. **Applicability.** - These rules shall apply to the all the Private Professional Colleges (PPC) opened after permission by the Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh.
3. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,
  - (a) "**Non-Resident Indian (in short N.R.I.)**" shall have the same meaning as defined/declared in Laws/Rules/Notification/Orders issued by the Central Government;
  - (b) "**Private Professional College (in short P.P.C.)**" means Medical/Dental/ Nursing/ Physiotherapy or by whatever name called, run by a private management/company/trust/body and affiliated to Pt. Deen Dayal Upadhyah Memorial Health Sciences Ayush University, Raipur;
  - (c) "**Reservation Policy**" means the reservation policy of the State Government for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other-Backward Classes and Women, from time to time.

**4. Special provision for admission in private professional college (PPC) of non-resident Indians.-**

- (1) Each Private Professional College (PPC) may fill 15% seats of the total seats by Non-Resident Indian (NRI) on basis of their merit amongst NRI category.
- (2) Fraction after calculation shall be rounded off to the next higher numeral in the favor of the concerned Private Professional College (PPC).
- (3) Student admitted against NRI category shall have to pay in foreign currency.
- (4) Each Private Professional College (PPC) shall declare in advance in website and other publicity means to this effect.
- (5) Reservation policy of the State shall also be applicable.
- (6) Each Private Professional College (PPC) shall admit the student in NRI quota before 10 days of the last date of admission, which is closing date for NRI category. After this closing date the seats will be declared empty and shall be converted as open category.

**5. Removal of difficulties.** - In case any difficulty arises in executing these rules, the matter shall be referred to Director, Medical Education who shall decide the case after approval by Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Health and Family Welfare. The Decision of Directorate of Medical Education (DME) shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R. K. TANDAN, Additional Secretary.



ITEM NO.8

COURT NO.2

SECTION

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A  
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Writ Petition (Civil) No.689/2017

CONSORTIUM OF DEEMED UNIVERSITIES IN  
KARNATAKA (CODEUNIK) & ANR.

Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

Respondent(s)

Date : 22-08-2017 This petition was called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRA  
HON'BLE MR. JUSTICE KURIAN JOSEPH  
HON'BLE MR. JUSTICE AMITAVA ROY

For Petitioner(s) Dr. Rajeev Dhawan, Sr. Adv.  
Ms. Farah Fathima, Adv.  
Mr. Mahesh Thakur, AOR

For Respondent(s) Mr. P.S. Narasimha, ASG  
Ms. Arunima Dwivedi, Adv.

Mr. Gaurav Sharma, Adv.  
Ms. Amandeep Kaur, Adv.  
Mr. Prateek Bhatia, Adv.  
Mr. Dhawal Mohan, Adv.  
Ms. Deepeika Kalia, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following  
O R D E R

Heard Dr. Rajeev Dhawan, learned senior counsel  
along with Ms. Farah Fathima, learned counsel for the  
petitioners, Mr. P.S. Narasimha, learned Additional Solicitor  
General for the Union of India and Mr. Gaurav Sharma, learned  
counsel for the Medical Council of India.

The matter was listed today for consideration of the filling up of NRI quota seats. Dr. Rajeev Dhawan, learned senior counsel appearing for the petitioners has drawn our attention to the letter circulars dated 13<sup>th</sup> July, 2017 and 28<sup>th</sup> July, 2017, issued by the Directorate General of Health Services. According to him, the said communications create an anomalous situation as a consequence of which the description of NRI has become extremely difficult. He has drawn our attention to a passage from P.A. Inamdar vs. State of Maharashtra (2005) 6 SCC 537, wherein the Constitution Bench has held thus:-

"Here itself we are inclined to deal with the question as to seats allocated for Non-Resident Indians ('NRI', for short) or NRI seats. It is common knowledge that some of the institutions grant admissions to a certain number of students under such quota by charging a higher amount of fee. In fact, the term 'NRI' in relation to admissions is a misnomer. By and large, we have noticed in cases after cases coming to this Court, neither the students who get admissions under this category nor their parents are NRIs. In effect and reality, under this category, less meritorious students, but who can afford to bring more money, get admission. During the course of hearing, it was pointed out that a limited number of such seats should be made available as the money brought by such students admitted against NRI quota enables the educational institutions to strengthen their level of education and also to enlarge their education activities. It was also pointed out that people of Indian origin, who have migrated to other countries, have a desire to bring back their children to their own country as they not only get education but also get reunited with Indian cultural ethos by virtue of being here. They also wish the money which they would be spending elsewhere on education of their children should rather reach their own motherland. A limited reservation of such seats, not exceeding 15%, in our opinion, may be made available to NRIs depending on the discretion of the management subject to two conditions. First, such seats should be

utilized bona fide by the NRIs only and for their children or wards. Secondly, within this quota, the merit should not be given a complete go-by. The amount of money, in whatever form collected from such NRIs, should be utilized for benefiting students such as from economically weaker sections of the society, whom, on well defined criteria, the educational institution may admit on subsidized payment of their fee. To prevent misutilisation of such quota or any malpractice referable to NRI quota seats, suitable legislation or regulation needs to be framed. So long as the State does not do it, it will be for the Committees constituted pursuant to the direction in Islamic Academy to regulate."

Submission of learned senior counsel is that the word "wards" used in the said paragraph should be understood in a broader compass and be applied in a wider spectrum. He has also drawn our attention to the decision rendered in Ruchin Bharat Patel vs. Parents' Association for the M/D Students and Others in I.A. Nos.9-10 & 11-12 in Civil Appeal No.4480 of 2006, wherein this Court after referring to various aspects, has held thus:-

"Normally, the admissions to the medical colleges should have been finally concluded before 30<sup>th</sup> September. This year's admission is long overdue and if this 15% of the students are not allowed to be admitted under NRI quota there may be financial loss to these college and the seats shall also go waste. In view of the peculiar circumstances of the case, for this year we are taking a practical view of the situation and we feel that the students to these colleges may be admitted under the following directions and we make it clear that this is exclusively for this year only as a one time arrangement because of the peculiar circumstances of the case:-

"1) The students be admitted as NRIs in NRI quota as against 15%; At least one of the parents of such students should be an NRI and shall ordinarily be residing abroad as an NRI;

2) The person who sponsors the student for admission should be a first degree relation of the student and should be ordinarily residing abroad as an NRI;

3) If the student has no parents or near relatives or taken as a ward by some other nearest relative such students also may be considered for admission provided the guardian has bona fide treated the student as a ward and such guardian shall file an affidavit indicating the interest shown in the affairs of the student and also his relationship with the student and such person also should be an NRI, and ordinarily residing abroad."

Even if these parameters are applied and sufficient number of students are not available for this year as against admission to 15% quota, the colleges would be at liberty to fill up the remaining seats from the State list and if the number of candidates admitted as against 15% quota is very much less and the colleges are unable to raise sufficient funds, they would be at liberty to approach the Committee to restructure the fees."

In this regard our attention has been invited to a Division Bench decision of the High Court of Madhya Pradesh rendered in Anshul Tomar vs. State of M.P. and Others (2008) 2 MPLJ 450, wherein the High Court after referring to the authority in Ruchin Bharat Patel (supra) has referred to a set of guidelines drafted by Pravesh Niyantaran Samiti (Medical Education), Mumbai. The said guidelines read as follows:-

"Based upon the decision of Hon'ble Supreme Court referred herein above dated 13<sup>th</sup> November, 2006 has laid down a criteria for admission in NRI quota, the Samiti decides and resolves the criteria for granting the admissions in NRI quota, as under :

- ✓ 1) If the mother or father of student is NRI and residing abroad ordinarily, then, either of the situations so held will be

considered to be proper.

✓ 2) If the first degree relation of the student is NRI and residing abroad ordinarily, then in such circumstances also, qua this year, should be considered eligible. It is natural that such definition would include the real brother and sister over and above the mother-father of the first degree relation.

✓ 3) As per the definition revised by the Hon'ble Apex Court, interpretation of clause 3 thereof as not made limited but if made in a broad perspective, then, it is clear that the person who wanted to consider such student as ward (Palya), then, he be considered to be proper subject to compliance of the following conditions :

- a) He should be the nearest relation.
- b) In the definition of the nearest relation, committee has considered following relative having blood relations.
  - i) Real brother and sister of father i.e. real uncle and real aunt.
  - ii) Real brother and sister of mother i.e. real maternal uncle and maternal aunt.
  - iii) Father and mother of father i.e. grand father and grand mother.
  - iv) Father and mother of mother i.e. maternal grand father and maternal grand mother.
  - v) First degree-paternal and maternal cousins.
  - vi) Such person should be NRI.
- c) Such persons should ordinarily be residing abroad.
- d) Such person should have looked after such student as the guardian of the student and evidence to that effect

must have been produced before the committee by such person.

- e) There should be affidavit with aforesaid fact.

The Samiti directs the AMUPMDC and the Institute/Colleges to follow the above guidelines strictly while granting the admissions in NRI quota in respect of the First Year Health Science course for the academic year 2007-2008 and onwards."

After reproducing the said guidelines, the Division Bench of the High Court of Madhya Pradesh has held as under:-

"In view of the aforesaid, we are inclined to think that the term 'ward' has been given a broader meaning in *Ruchin Bharat Patel (supra)*. We have reproduced the guidelines of Mumbai Committee to show that they are in consonance with the guidelines set forth by *Ruchin Bharat Patel (Supra)*. Nothing has been placed on record to show that NRIs have acted in a mala fide manner.

Regard being had to the amplified meaning of the term 'ward' and in the absence of any mala fide and further on the foundation that the merit has not been completely given a go-bye, we are inclined to quash the decision of the Committee and hold that the admission of the petitioners under the NRI quota are valid and the petitioners are entitled to prosecute their studies under the said College."

On being asked, Mr. P.S. Narasimha, learned Additional Solicitor General has submitted that this Court may think of making any kind of interim arrangement subject to final adjudication of the controversy so that the same does not arise in future.

As presently advised, the principles set out in *Anshul Tomar (supra)*, shall be followed this year for the purpose of filling up of 15% NRI quota. Be it clarified, the

NRI quota shall include Overseas Citizens of India (OCI) and Persons of Indian Origin (PIO). The counseling shall be held and finalised by 31<sup>st</sup> August, 2017, in respect of this quota and, if for some reason or other, the counseling is not concluded by that date, the same shall be completed by 4<sup>th</sup> September, 2017. It needs no special emphasis to state that the present order is only applicable to the deemed universities and no other category of institution.

Let the matter be set out for final disposal on 23<sup>rd</sup> November, 2017.

(Chetan Kumar)  
Court Master

(H.S. Parasher)  
Assistant Registrar